

संयुक्त राष्ट्र की संस्था ने किया खुलासा, कोरोना महामारी के दौरान निवेशक बड़े देश की 7.3 फीसदी आबादी ने क्रिप्टोकरंसी में पैसा लगाया

रिपोर्ट

संयुक्त राष्ट्र/नई दिल्ली, एजेंसी। कोविड-19 महामारी के दौरान दुनियाभर में क्रिप्टोकरंसी का इस्तेमाल अभूतपूर्व दर से बढ़ा है। इस दौरान भारत में भी क्रिप्टोकरंसी में निवेश करने वालों की तादाद बढ़ी है। भारत में सात फीसदी से अधिक आबादी के पास डिजिटल करंसी है। यह खुलासा संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में किया गया है।

यह स्थिति तब है जब केंद्र सरकार ने अब तक क्रिप्टोकरंसी को कानूनी मान्यता नहीं दी है और आरबीआई इस पर पूरी तरह से प्रतिबंधित करने के पक्ष में है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2021 में क्रिप्टोकरंसी रखने वाली आबादी की हिस्सेदारी के लिहाज से 20 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में से 15 विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाएं थीं। विकासशील देश भी पीछे नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक ये डिजिटल मुद्राएं अस्थिर वित्तीय एसेट है, जो अपने साथ कई तरह जोखिम लेकर आती हैं।

सीएनजी और पीएनजी के दाम पर अंकुश की तैयारी

नई दिल्ली, एजेंसी। पेट्रोलियम मंत्रालय ने सीएनजी और पाइप वाली रसोई गैस (पीएनजी) के दामों में नरमी लाने के लिए प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को उद्योगों से शहर गैस वितरण कंपनियों की तरफ मोड़ने का आदेश दिया है। आयातित ईंधन के इस्तेमाल की वजह से पिछले एक साल में सीएनजी और पीएनजी के दाम 70 प्रतिशत बढ़े हैं।

मंत्रालय ने करीब तीन महीने पहले वाहन ईंधन सीएनजी और रसोई में इस्तेमाल होने वाले ईंधन पीएनजी की बढ़ी मांग को पूरा करने के लिए महंगी आयातित एलएनजी के इस्तेमाल का

कसीनो पर कर का फैसला जल्द

नई दिल्ली, एजेंसी। कसीनो और 'ऑनलाइन गेमिंग' पर कराधान को लेकर गठित राज्यों के वित्त मंत्रियों का समूह अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक-दो दिन में सौंप सकता है। सरकारी सूत्र ने यह जानकारी दी।

जीएसटी परिषद की इस महीने के आखिर या सितंबर की शुरुआत में बैठक होने की संभावना है। बैठक में मंत्री समूह की रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अध्यक्षता में गठित मंत्री समूह (जीओएम) ने पिछली रिपोर्ट में जीएसटी परिषद से छुड़दौड़, 'ऑनलाइन गेमिंग' और कसीनो के

‘भारत आर्थिक वृद्धि में सबसे आगे होगा’

नई दिल्ली, एजेंसी। महंगाई के बावजूद भारत चालू वित्त वर्ष में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होगा। सरकार के एक वरिष्ठ सूत्र ने यह बात कही। सूत्र ने कहा कि सरकार मुद्रास्फीति को काबू में लाने के लिए रिजर्व बैंक के साथ मिलकर लगातार काम कर रही है।

उन्होंने कहा, जमीनी स्तर पर जो जानकारी मिल रही है, उससे पता चलता है कि खाद्य तेल और कच्चे तेल के दाम नरम हुए हैं और मानसून अच्छा रहने का अनुमान है। इन सबको दुखते हुए आने वाले समय में मुद्रास्फीति को लेकर दबाव कम होने की उम्मीद है।

स्पेक्ट्रम के लिए भुगतान तिथि बढ़ी

नईदिल्ली, एजेंसी। दूरसंचार विभाग (डॉट) ने हाल ही में पूरी हुई 5जी स्पेक्ट्रम नीलामी में सफल बोली लगाने वाली कंपनियों के लिए भुगतान की तारीख 17 अगस्त तक बढ़ा दी है।

एक आधिकारिक आदेश के अनुसार मुंबई और महाराष्ट्र सर्किलों में 16 अगस्त को बैंक अवकाश होने के कारण देय तिथि को एक दिन बढ़ा दिया गया है। उल्लेखनीय है कि 5जी स्पेक्ट्रम नीलामी एक अगस्त को पूरी हुई और इसमें रिलायंस जिओ, अडाणी डेटा नेटवर्क्स, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने स्पेक्ट्रम हासिल किया था। इसमें 1.5 करोड़ रुपये के लिए बोलियां मिली हैं।

03 फीसदी से कम हिस्सेदारी कुल आबादी का शेयर बाजार के निवेश में

क्रिप्टो रखने में भारत से आगे हैं यह देश

संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूएनसीटीएडी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वर्ष 2021 में डिजिटल मुद्रा रखने के मामले में दुनिया के शीर्ष-20 देशों में भारत सातवें स्थान पर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि क्रिप्टोकरंसी रखने में सबसे आगे यूक्रेन है जहां 12.7 फीसदी आबादी इसे रखती है। रूस में 11.9, वेनेजुएला में 10.3, सिंगापुर में 9.4 और अमेरिका में 8.3 फीसदी लोगों के पास क्रिप्टोकरंसी है।

मौद्रिक संप्रभुता के लिए खतरा बताया

रिपोर्ट में आरबीआई के उस पक्ष पर मुहर लगाते हुए कहा गया है कि अगर क्रिप्टोकरंसी पैमेंट का माध्यम बनती है और गैर आधिकारिक रूप से घरेलू मुद्रा की जगह लेती है तो इससे देश की मौद्रिक संप्रभुता को खतरा पैदा हो सकता है। आरबीआई गर्वनर कई मौकों पर क्रिप्टोकरंसी को देश के वित्तीय ढांचे के लिए खतरा बता चुके हैं।

10 फीसदी से कम हिस्सेदारी कुल आबादी का म्यूचुअल फंड में

भारत में यह है स्थिति

पाबंदी चाहता है आरबीआई 1 आरबीआई देश में क्रिप्टोकरंसी पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने की सिफारिश कई बार कर चुका है। उसका कहना है कि क्रिप्टो कोई मुद्रा नहीं है। हालांकि इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है।

सरकार ने टैक्स लगाया

2 वर्ष 2022-23 के बजट में वित्त मंत्री ने क्रिप्टोकरंसी और एनएफटी को वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के तहत जोड़ा है। इनसे होने वाली कमाई पर 30% टैक्स लगा दिया गया है। एक फीसदी टीडीसी अलग से लगाया गया है।

आरबीआई की डिजिटल मुद्रा जल्द

3 इस साल के बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा योजना शुरू करने की घोषणा की थी। भारतीय रिजर्व बैंक इसे चरणबद्ध तरीके से थोक और खुदरा क्षेत्र में लागू करने की प्रक्रिया में है।

एलन मस्क ने टेस्ला में अपने 80 लाख शेयर बेचे

न्यूयॉर्क, एजेंसी। ट्विटर के साथ कानूनी लड़ाई से पहले टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने कंपनी में अपने करीब सात अरब डॉलर के शेयर बेच दिए हैं। मस्क गुरुवार को ने शेयर बाजारों को यह जानकारी दी।

मस्क ने बताया कि उन्होंने हाल के दिनों में टेस्ला इंक में अपने करीब 80 लाख शेयर बेचे हैं। टेस्ला और ट्विटर दोनों में ही मस्क सबसे बड़े शेयरधारक हैं। मस्क ने ट्वीट किया कि अगर ट्विटर सौदे को पूरा करने का दबाव बनाती है और कुछ इक्विटी साझेदार साथ नहीं आते हैं तो टेस्ला के शेयरों की आपातकालीन बिक्री से बचने के



लिए ऐसा करना जरूरी है। मस्क ने आरोप लगाया था कि कंपनी ट्विटर के फर्जी खातों की संख्या के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं दे सकी, जिसके चलते उन्होंने यह सौदा रद्द किया। मस्क ने इस साल की शुरुआत में करीब 44 अरब डॉलर में ट्विटर के अधिग्रहण का समझौता किया था।

आईटी-बैंकिंग शेयरों से सेंसेक्स में उछाल

मुंबई, एजेंसी। सूचना प्रौद्योगिकी, बैंकिंग और वित्तीय शेयरों में जोरदार लिवाली तथा विदेशी कोषों के सतत प्रवाह से गुरुवार को सेंसेक्स 515 अंक चढ़कर 59,000 अंक के पार निकल गया। बीएसई का तीस शेयरों वाला सेंसेक्स 515.31 अंक यानी 0.88 प्रतिशत की बढ़त के साथ 59,332.60 अंक पर बंद हुआ।

वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 124.25 अंक 0.71 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 17,659 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स के शेयरों में एक्सिस बैंक में सबसे अधिक 2.75 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

DiGiSPICE

DiGiSPICE Technologies Limited

Regd. Office: 622, 6th Floor, DLF Tower A, Jasola Distt. Centre, New Delhi -110025

CIN No.: L72900DL1986PLC330369

Tel.: +91 11 41251965; **Email:** complianceofficer@digispice.com; **Website:** www.digispice.com

Extract of Unaudited Consolidated Financial Results for the quarter ended June 30, 2022				(Rs. in Lakhs)
Particulars	For the Quarter ended 30.06.2022 (Unaudited)	For the Year ended 31.03.2022 (Audited)	For the Quarter ended 30.06.2021 (Unaudited)	
Total Income from operations	26,330.16	99,060.62	22,866.22	
Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(265.16)	1,443.93	(89.52)	
Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(265.16)	1,343.93	(89.52)	
Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items and/or Non controlling Interest)	(434.24)	542.44	(242.15)	
Total Comprehensive Income/(Loss) for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income/(Loss) (after tax)]	(393.48)	589.93	(179.41)	
Equity Share Capital (Face value Rs 3/- per share)	6,149.57	6,146.00	6,079.57	
Reserves (Excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of Previous year)		18,580.88		
Earnings per share (for continuing and discontinued operations) (of Rs 3/- each)				
Basic:	(0.19)	0.24	(0.11)	
Diluted:	(0.19)	0.23	(0.11)	

Notes:

1. Key Standalone Financial Information is given below:

Particulars	For the Quarter ended 30.06.2022 (Unaudited)	For the Year ended 31.03.2022 (Audited)	For the Quarter ended 30.06.2021 (Unaudited)
Net Sales / Income from Operation	809.02	11,252.30	2,137.94
Profit/(Loss) before tax	(667.28)	(316.38)	(228.66)
Net Profit/(Loss) after tax	(667.28)	(385.02)	(236.91)

2. The above is an extract of the detailed format of quarterly and year ended financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on August 09, 2022 and August 10, 2022. The full quarterly unaudited financial results are available on the Stock Exchange website(s) www.bseindia.com, www.nseindia.com and on the Company's website www.digispice.com.

By order of the Board
For DiGiSPICE Technologies Limited

Dated: August 10, 2022

Place: Noida

Rohit Ahuja
Executive Director

आयकरदाताओं को अटल पेंशन योजना का लाभ नहीं

बदलाव

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार ने अटल पेंशन योजना में बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत आयकरदाता अब इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। नया नियम 01 अक्टूबर 2022 से लागू होगा। वित्त मंत्रालय की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह बदलाव आयकरदाताओं के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। यह योजना सरकार ने 2015 में शुरू की थी और मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के लोगों पर केंद्रित है।

वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार कोई भी नागरिक जो आयकर भरता है या पहले कभी भर चुका है, वह 01 अक्टूबर 2022 से अटल पेंशन योजना का लाभ नहीं उठा सकता है। मंत्रालय ने यह भी साफ किया है कि किन लोगों को आयकर दाता माना जाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति, जिसके ऊपर आयकर की धारा 1961 के तहत आयकर देनदारी बनती है, उसे आयकर दाता माना जाएगा।

तत्काल बंद हो जाएगा खाता :

वित्त मंत्रालय के अनुसार यदि कोई



01 अक्टूबर 2022 से लागू होगा नया नियम

दूसरी बार हुआ संशोधन

इस योजना को सरकार की तरफ से 2015 में शुरू किया गया था। सरकार ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को ध्यान में रखकर शुरू किया था लेकिन बाद में इसमें बदलाव किया गया। अब 18 से 40 साल तक का कोई भी भारतीय नागरिक इसमें पंजीकरण करा सकता है। एक बार फिर इस योजना में बदलाव के बाद अब आयकरदाता इसका हिस्सा नहीं बन सकते।

ग्राहक एक अक्टूबर या उसके बाद इस योजना से जुड़गा और बाद में वो आयकरदाता पाया जाता है तो उसका खाता तत्काल बंद कर दिया जाएगा। साथ ही उस समय तक जमा पैसे उसके खाते में वापस कर दिए जाएंगे।



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)

जी-5 एवं 6, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075

30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही के लिए अनंकेक्षित एकल वित्तीय परिणाम

(सेबी परिपत्र सं. सेबी/एचओ/डीडीएचएस/सीआईआर/2021/637 दिनांक 05 अक्टूबर, 2021 के अनुसार)

(₹. करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही		समाप्त वर्ष	
		30 जून, 2022	30 जून, 2021	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
		अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अंकेक्षित
1.	प्रचालनों से कुल आय	मान्य नहीं	मान्य नहीं	मान्य नहीं	मान्य नहीं
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, असाधारण एवं/अथवा विशिष्ट मदों से पहले)	(92.23)	(41.48)	(587.87)	(467.26)
3.	कर पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, असाधारण एवं/अथवा विशिष्ट मदों के बाद)	(102.54)	(50.98)	(625.65)	(497.90)
4.	कर परचात अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, असाधारण एवं/अथवा विशिष्ट मदों के बाद)	(102.54)	(50.98)	(625.65)	(497.90)
5.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए लाभ/(हानि) (कर परचात) तथा अन्य व्यापक आय के बाद (कर परचात)*)	(102.54)	(50.98)	(625.65)	(497.90)
6.	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (शेयरधारक का कोष)***	3,93,117.34	2,81,895.87	3,36,595.87	2,61,113.53
7.	अधिशेष (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित छोड़कर)	-	-	-	-
8.	नेटवर्थ (6-7)	3,93,117.34	2,81,895.87	3,36,595.87	2,61,113.53
9.	प्रदत्त ऋण पूंजी/बकाया ऋण	3,44,333.14	3,16,651.24	3,48,907.23	3,07,162.61
10.	बकाया प्रतिदेय अधिमान्य शेयर्स	-	-	-	-
11.	ऋण इक्विटी अनुपात **	0.88	1.12	1.04	1.18
12.	प्रति शेयर अर्जन (प्रत्येक ₹./- का) (निरंतरता एवं गैर-निरंतरता प्रचालनों हेतु) 1. बैसिक 2. डाल्यूटेड	मान्य नहीं	मान्य नहीं	मान्य नहीं	मान्य नहीं
13.	पूंजी विमोचन संचित कोष	-	-	-	-
14.	डिबेंचर विमोचन संचित कोष	-	-	-	-
15.	ऋण सेवा कवरेज अनुपात	मान्य नहीं	मान्य नहीं	मान्य नहीं	मान्य नहीं
16.	ब्याज सेवा कवरेज अनुपात	मान्य नहीं	मान्य नहीं	मान्य नहीं	मान्य नहीं

*लेखा नीति के आधार पर निवल व्ययों को पूंजीकृत किया गया है

ऋण इक्विटी अनुपात = बकाया ऋण/शेयरधारकों की निधि***

***प्राधिकरण भारत सरकार की ओर से सम्पत्ति धारण करता है, इसलिए परिचालनों से कोई आय नहीं है।

****शेयरधारक की निधि = पूंजी आधार, उप कर निधि, अतिरिक्त बजटीय समर्थन, टोल प्लाजा के रखरखाव व्यय तथा रिजर्व और अधिशेष/लाभ एवं हानि खाते के बकाया ऋण के परचात जमा टोल की वापसी के बाद की कुल राशि

क) उपरोक्त एलओडीआर विनियम के विनियम 52 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों के पास दाखिल किए गए तिमाही/ वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों का पूरा प्रारूप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यानी (www.bseindia.com तथा www.nseindia.com) पर तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की वेबसाइट (https://nhai.gov.in) पर उपलब्ध है।

ख) एलओडीआर विनियम के विनियम 52(4) में संदर्भित अन्य लाइन मदों के लिए प्रासंगिक प्रकटन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में किए गए हैं और इसे वेबसाइटों (www.bseindia.com तथा www.nseindia.com) पर प्राप्त किया जा सकते हैं।

प्राधिकरण के बोर्ड के लिए तथा उसकी ओर से

तिथि: 11.08.2022	ह/-	ह/-
स्थान: नई दिल्ली	सदस्य (वित्त)	अध्यक्ष

सड़कों ही नहीं, राष्ट्र निर्माण भी

SpaceX gets Pentagon nod to use recyclable boosters

It can now use these boosters on US's Falcon Heavy rocket to launch top-secret spy satellites



This solidifies Musk's relationship with the Pentagon eight years after he sued to break into the military launch market.

Elon Musk's SpaceX has won certification from the Pentagon's Space Force to use recyclable boosters on its Falcon Heavy rocket to launch top-secret spy satellites, according to the service.

It may give Musk's insurgent company at least a temporary edge in its latest competition with a Boeing-Lockheed joint venture that once had a monopoly on the Defense Department's satellite launches.

Qualifying to use money-saving recycled boosters for launches of the nation's largely classified surveillance, early warning and intelligence satellites solidifies Musk's relationship with the Pentagon eight years after he sued to break into the military launch market.

By contrast, the Air Force is still reviewing certification for the United Launch Alliance — the joint venture of top defense contractors Boeing Co. and Lockheed Martin Corp. — to use its Vulcan rocket with a new US-made motor from Jeff Bezos's Blue Origin LLC. The alliance plans a test launch in December.

The new motor would replace the Russian-made RD-180, which is reliable but was already politically controversial in Washington years before Russia's current war in Ukraine.

The certification for SpaceX, which was issued in June but not previously disclosed — allows the recyclable first-stage side boosters to be used in sensitive national security launches requiring power performance beyond that of the company's original Falcon 9. The Space Force found that the "recovery, refurbishment, and launch of SpaceX boosters utilises well-established processes," the service said in a state-

ment.

The first classified National Security Space Launch mission using a Falcon Heavy with refurbished boosters is scheduled for sometime from October to December, according to the Space Force. It's a mission to launch a satellite for the National Reconnaissance Office, which develops and manages spy satellites, according to a previous Space Force statement.

SpaceX, which didn't reply to a request for comment, has launched more than 100 missions using the Falcon 9 with reusable boosters, most of them commercial.

The reuse of previously flown boosters on Falcon 9 missions has "saved the US Space Force more than \$64 million for GPS III missions and avoided additional costs for requirements changes while adding manifest flexibility for both the launch provider and our war-

fighters," Walter Lauderdale, chief of the Falcon Division within the Space Systems Command's "Assured Acap to Space" organization, said in a statement.

First announced in 2011, Falcon Heavy is SpaceX's reusable "super heavy" launch vehicle that lets the closely held company bid on heavier payloads, such as larger commercial satellites as well as national security missions.

Tripling Power

Falcon Heavy is basically three Falcon 9 rockets strapped together, tripling the launch power. While one Falcon 9 has nine engines in its first stage, Falcon Heavy has 27. That's more than five million pounds of thrust at liftoff, which SpaceX says is equivalent to that of about 18 Boeing 747 airplanes.

“The certification to use previously flown side boosters further supports

the alternative business model SpaceX has used to break into the space launch market," said Todd Harrison, a space systems analyst with Meta Aerospace who's followed SpaceX's Air Force programs for years.

It's "a commercially driven innovation that SpaceX pursued before the government even realized it was both achievable and advantageous," Harrison said. "So I think this certification is an implicit endorsement of SpaceX's approach to innovation."

The Air Force is currently reviewing its acquisition strategy of the third competitive phase for 39 national security launches of US military and intelligence satellites in fiscal years 2025 through 2027. United Launch Alliance won 25 of the 42 military launches planned for Phase 2 through fiscal 2024, with the other 17 going to SpaceX.

RajCOMP Info Services Limited (RISL) C-Block, 1st Floor, Yojana Bhawan, Tikali Marg, C-Scheme, Jaipur.			
RISL invites bids from the eligible bidders for the following:			
Particulars		Estimated Cost/EMD	Start of sale /Last date
NIS No. / Unique bid no.			
3385/10-08-2022 RIS2232SLOB 00046	Hiring of Technical Experts to work on Big Data Stack and OEM Annual Technical Support for Big Data Annual Stack	Rs. 14,50,00,00/- Rs. 29,00,00/- LACS	02.09.2022 20.09.2022
Bids can be seen on the websites http://risl.rajsan.gov.in, http://spec.rajsan.gov.in & http://ddcc.rajsan.gov.in. Bids are to be submitted through http://eproc.rajsan.gov.in for http://samidc.rajsan.gov.in. Bids are to be submitted through http://eproc.rajsan.gov.in for http://samidc.rajsan.gov.in.			
RajSamdrc/2022/6246			SA (TJ, DIR.)

The West Bengal Power Development Corporation Limited
(A Govt. of West Bengal Enterprise)
Corporate Identity No.: U-1014751935-SC039154
Registered & Corporate Office: Bidyut Unnayan Bhavan
Plot No.: 3/C, L-4, Block, Sector-13, Bidhannagar, Kol-700106

Notice Inviting E-Tender

Ref. No.: WBPDCL / Tend.-Add-22-23/Corp-CC-85 Date: 08.08.2022
NIT No.: WBPDCL/Corp/NIT/15/17/22-23 Dated: 02.08.2022

E-Tenders in prescribed format are invited at <http://wbtdenders.gov.in>, by the General Manager (M&C), WBPDCL, from eligible agencies/companies for "Construction of Concrete Pathways at both ends along the left and right side of the existing 11KV line at the intersection of a National Drain under WBPDCL in the district of Paschim, Jharkhand, Tender Document Download Start Date: 08.08.2022 from 17.00 hrs, Bid Submission End Date: 16.08.2022 at 16.00 hrs, Contact Person: Smt. Subhasita Bhattacharya, a Manager (Civil) M&C, Tender No: 9475851541. E-mail: subhatacharya@wbpdcl.co.in For details please visit <http://wbtdenders.gov.in>

ICA:14426.22/22

CENTRAL RAILWAY
E-Tender Notice No. NCP/Elec/
TRD/2022-23/09R, Date 01.08.2022
Name of work: Provision of an Anti
 bird disc for prevention of bird falls
 and melting/parting of catenary
 wire under catenary suspension
 clamp on Nagpur Division.
Estimated cost of work: Rs.
 58,48,350.00 **Earnest Money:**
Deposit: Rs. 1,17,000.00 **Last**
date & time for submission of
tender: 30.08.2022 at 15.00
Hours. Website Address: Details
 on Railway website
www.irps.gov.in
Sr. DEE (TRD), Nagpur
Rail Madad Helpline: 139 NCP-116

James Warren Tea Limited				
Corporate Identity Number (CIN) : L15491AS2009PC009345				
Registered Office : Choodan Tea Estate, P.O. Borahateng, Dist. Tinsukia, Assam (Pin-786150) Tel: 03759-2434102				
Corporate Office : Aspirations Village, 12, Preeto Street, Kolkata 700071, Tel: 91-33-40341000, Fax: 91-33-40341015				
E-mail: swt@jwte.com , www.jameswarrentea.com				
Extract of Un-audited Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2022				
Sl. No.	Particulars	3 Months ended on 30.06.2022	3 Months ended on 30.06.2021	Year Ended on 31.03.2022 (in Lakhs)
		Unaudited	Unaudited	Unaudited
1	Total Income from operations	-	-	11,643.58
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	800.84	598.29	940.10
3	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	800.84	598.29	940.10
4	Net Profit/(Loss) for the period (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	764.84	565.35	825.20
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)	764.84	633.72	1,259.71
6	Equity Share Capital	440.00	524.27	440.00
7	Other Equity (excluding Reserve/Retainage)	-	-	-
8	Earnings per share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)**	-	-	-
	Basic:	17.38	10.84	15.77
	Diluted:	17.38	10.84	15.77



YAMA
FUTURE IS HERE

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्रथम तल, कॉमर्सियल कॉम्प्लेक्स, सैक्टर-ओमेगा-1 (पी-2) ग्रेटर नोएडा
Toll Free No. 1800180296, वेबसाइट : www.yamunaxpresswayauthority.com

पत्रांक – आईईएफए / भूलेख / 492 / 2022 दिनांक 10.08.2022

सार्वजनिक सूचना

जन सामान्य को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय, आबादी भूमि आवंटन विनियमावली 2010 का प्राधिकरण बोर्ड की 70वीं बॉर्ड बैठक में संशोधित नियमावली के बिन्दु संख्या 5.5 के क्रम में ग्राम आछेरपुर, ग्रामान दनकोर, जलपट गौतमबुद्धनगर में अर्जन /बेमोस से क्रय भूमि के सापेक्ष 07 प्रतिशत आबादी भूमि आवंटित किये जाने हेतु प्राप्त व्यक्तियों की अनतिम सूची तैयार कर निम्न स्थानों पर सार्वजनिक सूचना हेतु प्रदर्शित की गई है।

- नोटिस बोर्ड, मुख्य प्रशासनिक कार्यालय, पी-2, ओमेगा - 1, ग्रेटर नोएडा।
- नोटिस बोर्ड भूलेख विभाग, यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण।
- सामुदायिक केंद्र भवन / प्राथमिक विद्यालय / पंचायत भवन, ग्राम आछेरपुर।
- प्राधिकरण की वेबसाइट पर।

आबादी विनियमावली के बिन्दु संख्या 5.5 के अनुसार परीक्षित सूची में वर्णित व्यक्ति विवरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह लिखित आपत्ति प्रकाशन के दिनांक से 15 दिनों के अंदर यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है।

विशेष कार्यधिकारी



GUJARAT METRO RAIL

CORPORATION (GMRC) LIMITED

(SPV of Govt. of India and Govt. of Gujarat)

Block No.1, First Floor, Karmayogi Bhavan, Sector 10/A,
Gandhinagar: 382010, Gujarat. (CIN): U60200GJ2010SGC059407

TENDER NOTIFICATION No: GMRC/S&T/AFC-01/AHMEDABAD/PH-2/2022

Dated : 12.08.2022

E-Tenders are invited from reputed and experienced Contractors for the following tender :


Tender Name	Tender Fees
Request for Proposal for Design, Manufacture, Supply, Installation, Testing and Commissioning, Maintenance of NCMC EMV & QR Code based Automatic Fare Collection System based on PPP Revenue model for Ahmedabad Metro Rail Phase-2	INR 25,000/-

Interested bidders are requested to visit <https://gmrc.nprocure.com> for eligibility criteria, applying / downloading the tender document.

Last date and time for Bid Submissions is 15:00 Hrs on 27.09.2022

Any alterations in Eligibility Criteria cum Qualification Requirements, and terms of the Tender Document, or any amendment to the Tender Document, etc. will be uploaded on <https://gmrc.nprocure.com> and GMRC's Website www.gujaratmetrorail.com without any obligation or press notification or other proclamation.

Sd/-
Managing Director,
GMRC, Gandhinagar

 BSES Yamuna Power Limited	BSES Yamuna Power Limited, Delhi ... A joint venture with Govt. of NCT of Delhi				
NOTICE INVITING TENDER					
Date: 12.08.2022					
Sealed tenders under two Bid System (Unpriced & Priced) is invited for following jobs:					
NIT No.	Brief Description	Estimated Cost (₹)	Cost of EMD (₹)	Due Date & Time of Submission	Date & time of Bid opening
CMC/BY/22-23/ RS/MD/33	SURVEY, DESIGN, ENGINEERING, SUPPLY, ERECTION, TESTING, & COMMISSIONING OF NEW 33KV SWITCHGEAR PANELS INCLUDING MINOR CIVIL WORKS AND DISMANTLING OF EXISTING EQUIPMENTS ON TURNKEY BASIS AT GB PANT GRID, DELHI	3.93 Crore	7.86 Lakh	31.08.2022 15:00 Hrs	01.09.2022 16:00 Hrs
CMC/BY/22-23/ RS/MD/34	SURVEY, DESIGN, ENGINEERING, SUPPLY, ERECTION, TESTING, & COMMISSIONING OF NEW 11KV SWITCHGEAR PANELS INCLUDING MINOR CIVIL WORKS AND DISMANTLING OF EXISTING EQUIPMENTS ON TURNKEY BASIS AT KAILASH NAGAR & DALLUPURA GRID, DELHI	6.66 Crore	6.66 Lakh	31.08.2022 15:00 Hrs	01.09.2022 16:30 Hrs
Cost of each Tender Documents: ₹ 1,180/- For details in respect of Equipment/BOM/Services, Qualifying requirements, Terms & conditions, purchase/submission of tender documents, corrigendum etc. please visit our website www.bsesdelhi.com -->Tenders--> BSES YAMUNA POWER LTD --> Open Tenders. Head (Contracts & Materials)					
Regd.Off: BSES Yamuna Power Ltd, Shakti Kiran Building, Karkardooma, Delhi-110032 CIN: U40109DL2001PLC115125 TEL: 011-41247411 Fax: 011-4124 7787 Website: www.bsesdelhi.com					

F. No. 19/1/2019 PR
Government of India
Ministry of Finance
Department of Financial Services

3rd Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001

Inviting applications for the post of Chairperson in Pension Fund
Regulatory and Development Authority (PFRDA), New Delhi

Applications are invited for the post of Chairperson, Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA), New Delhi, which has a tenure of period 5 (five) years or up to 65 years of age, whichever is earlier.

The pay and allowances of the Chairperson shall be Rs. 4.50 lakh consolidated per month without facility of house and car or any other allowance. The particulars of the post and eligibility conditions are given on the Ministry's website <http://financialservices.gov.in> as well as on PFRDA's website <http://www.pfrda.org.in>. The last date and time for receiving the completed applications is **05.09.2022 till 5.30 P.M.** Applications clearly demonstrating eligibility may be submitted at the address indicated below:

Ms. Sushma Kindo,
Joint Director, Pension Reforms Section
Department of Financial Services,
Ministry of Finance, Government of India,
Room No. 28-B, 3rd Floor, Jeevan Deep Building,
Parliament Street, New Delhi-110001
Tele No. 011-23360250

CBC 15102/12/0009/2223